पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) . 1977 में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये :—

(1) पेट्रोलियम मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ;

(2) दो मंत्रालयों के कार्य निष्पादन बजट ;

(3) पाइप लाइन जांच आयोग की रिपोर्ट ;

(4) तेल मूल्य समिति की रिपार्ट।

(5) इंडियन फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स, 1976-77;

(6) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकलस्टेटिस्टिक्स, 1976-77 ;

(7) भारत मे रसायन उद्योग की स्थिति ;

(8) इंडियन पेट्रोलियम एण्ड पेट्रोकैमिकल्स स्टेटिस्टिक्स-1976 ;

(9) इंडियन पेट्रोलियम एण्ड पेट्रोकैमिकल्स स्टेटिस्टिक्स-(द्विवार्षिक फोल्डर) ।

प्रथम तीन प्रकाशनों को हिन्दी में भी निकाला गया था। चौथे प्रकाशन का हिन्दी रूपान्तर छप रहा है । अन्य प्रकाशनो मे अधिकतर सांख्यकीय आकडे है और उनका परिचालन सीमित है । ऐसे प्रकाशनों को केवल अंग्रेजी में निकाला जाता है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Six-point programme of N.C.C.R.S.

7974. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation from the Indian Railways Loco Mechanical Staff Association (Northern Railway) to implement the six-point programme of NC.C.R.S.; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Recently, large number of representations signed by individual employees belonging to this Association have been received. One of the demands contained in them is about starting negotiations on the six-point charter of demands.

(b) A statement giving Government's reaction to the 6 point charter of demands is attached.

Statement

(i) *Bonus*.—The question regarding payment of bonus to the employees of the Govt. departmental undertakings will be considered by the Govt. after receipt of the report of the Study Group recently appointed by Govt. to evolve a national policy on wages, incomes and prices in all sectors, after a comprehensive study.

(ii) *Dearness Allowance*.—This is a general issue which cannot be considered by the Ministry of Railways alone since it is a wider issue on which the Government has to take a decision, covering all Central Government employees. During the last few months, two more instalments of Dearness allowance have been sanctioned.

(iii) *Parity in wages with other Central Govt. undertakings*.—This is

intimately linked with the question of wages, incomes and prices policy which is being studied in depth by the Boothalingam Study Group, recently appointed by Govt.

(iv) *Decasualisation.*—While it is not possible to achieve the ideal stage of complete decasualisation immediately, steps have been and are being taken to redress grievances of casual labour in the matter of their absorption etc.

(v) *Supply of subsidised foodgrains.*—The issues raised cannot be considered by the Ministry of Railways alone since Govt. has to take a decision covering all Central Government employees.

(vi) *Railwaymen as Industrial workers.*—Already, Railway employees are governed by the provisions of the Industrial Disputes Act. However, in respect of the terms and conditions of service, they are traditionally treated as Government servants as basically Railways are in the nature of a public service and are run directly by Government because of their social and strategic importance.

असिस्टेंट मैडिकल आफिसर (दंत चिकित्सक) की पदोन्नति

7975. श्री बृजराज सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में असिस्टेंट मैडिकल आफिर (दंत चिकित्सक) के पदोन्नति के नियम क्या हैं और इस समय कुल दंत चिकित्सकों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनें को श्रेणी एक के पदों पर पदोन्नति किया गया ;

(ख) क्या वर्ष 1957 से 1976 तक सहायक दंत चिकित्सकों और अन्य मैडिकल आफिसरों के लिये संयुक्त वरिष्ठता थी और वर्ष 1976 में दंत चिकित्सक वरिष्ठता को समाप्त करनें के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या शर्मा आयोग ने सिफारिश की है कि असिस्टेंट मैडिकल आफिसर (दंत चिकित्सक) को 700–1600 के वेतन मान में श्रेणी एक पर पदोन्नति किया जाना चाहिये और क्या उक्त सिफारिश को इस बीच क्रियान्वित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) तीसरे वेतन आयोग ने सहायक चिकित्सा अधिकारी (दन्त चिकित्सक) के लिए सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 1 के संशोधन वेतन मान की सिफारिश नही की है । वे आगे मंडल चिकित्सा अधिकारियों के रूप मे पदोन्नति के पात्र भी नही हैं । सहायक चिकित्सा अधिकारियो (दन्त चिकित्सा) की कुल संख्या 22 है ।

(ख) जी नही ।

(ग) शर्मा आयोग ने 1–8–1968 से पूर्व नियुक्त दन्त शल्य चिकित्सकों के लिए 700–1600 रु० के ग्रेड की सिफारिश की थी, किन्तु इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है ।

Complaints against drilling programme in West Bengal

7976. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that complaints have been made against the drilling programme in West Bengal both regarding on-shore and off-shore prospecting of Oil and Gas;

(b) if so, facts about the depth of drilling made so far in Diamond Harbour, Golsy and other areas; and

(c) whether it has been ascertained that if drillings to greater depths could be made Oil or Gas would have been struck?